

एक नज़र

दिल्ली के एलजी अनिल बैजल का अचानक इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला



नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राश्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जनकारी के मुताबिक उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। नजीब जंग के बाद वह दिल्ली के एलजी बने थे। उन्हें दिसंबर 2016 में उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। प्रशासन को लेकर अक्सर उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मतभेद रहते थे। 30 दिसंबर 2021 को बैजल का कार्यकाल पूरा हो गया था लेकिन उन्हें सेवा में विसर्ग दिया गया था। वह पांच साल तक दिल्ली के उपराज्यपाल और एलजी के बीच विवाद होता रहा है। बैजल 1969 बैच के आईएस अफिसर रहे हैं। वह दिल्ली के 21 वें उपराज्यपाल बनाए गए थे। अबल विहारी वाजपेयी की सकार में वह केंद्रीय गृह सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। यह सचिव रहने के दौरान ही उन्होंने विकास बैदी को कार्यालय की थी और उन्हें औंक जल्स के पद से हारा दिया था। उनपर जेल के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था। अनिल बैजल ने कहा है कि मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पद संभालने वह दिल्ली विकास प्राधिकार के उपराज्यपाल बनाए गए थे। साल 2006 में वह शहरी विकास मंत्रालय अवधि के सचिव पद से सेवानिवृत हुए थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू नेशनल अवधि मिशन से जुड़े रहे।

5जी से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे : दूरसंचार सचिव

नयी दिल्ली। दूरसंचार सचिव के राजसमन ने बुधवार को कहा कि 5जी सेवाओं की शुरुआत से नई प्रौद्योगिकीयों के लिए उत्त्युक कौशल की जरूरत होगी, जिससे बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राजसमन ने दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद (टीएसएसपी) के एक कार्यक्रम में कहा कि भारतनेट से लेकर अतिक्ष दूरसंचार और 5जी से लेकर ब्रॉडबैंड सेवाओं में बड़े पैमाने के लिए उद्योग देने का उपराज्यपाल बनाने पर अन्य देने का आँखन भी किया। सचिव ने कहा, "उद्योग के मामलों या तीरीकों में बढ़ोत्तरी के साथ 5जी सेवाओं में बढ़द होगी तथा प्रौद्योगिकी की प्रकृति और क्षमता की पेशकश के चलते कौशल के एक नई उत्कृष्णन भी खुलेगी।" दूरसंचार विभाग के शीर्ष अधिकारी ने 5जी की शुरुआत से अंगमेंटेड रियलटी, बृहुल अंटर्निटी और इंटरनेट से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ोंगे। उन्होंने कहा कि फिल्स्ट वायरलाइन ब्रॉडबैंड के भी तेजी से बढ़ोंगे की काफी गुंजाइश है। अपी इस क्षेत्र में पहुंच का दायरा काफी सीमित है। वह क्षेत्र भी दो अंकों वृद्ध हासिल कर सकता है।

सड़क दुर्घटना में दो बच्चों की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

नोएडा। नोएडा के थाना दातरी क्षेत्र के दादरी बाईपास के पास बुधवार दोपहर को एक कार के मोटरसायकिल को टक्कर मार देने से मोटरसायकिल सवार दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना जारिया क्षेत्र के लियाकती गांव के रहने वाले अफजाल अपनी पत्नी तथा तीन बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उन्होंने बताया कि जैसे ही वह दादरी बाईपास के पास पहुंच पैछे से आ रही एक कार का टायर फट गया और कार अनियन्त्रित होकर उनकी मोटरसाइकिल से टक्कर गई। उन्होंने बताया कि इस घटना में सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उत्तर ले जाया गया ताकि इस घटना को नियंत्रित करने के लिए अस्पताल ले जाया गया ताकि इसकी सूचना दी। जिसके बाद फायर बिग्रेड को फॉन किया गया। यौक पर पहुंची फायर बिग्रेड की पांच गाड़ियोंने दूरपारी मजिल पर स्थित न्यायाधीश की चैंबर में लौंग आग पर कुछ ही देर में कालू पा लिया। हालांकि न्यायाधीश के चैंबर में रुखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। इसके न्यायाधीश का निजी सामान भी शामिल है। अपी फायरकर्मी ने पुलिस दोनों मौके पर हैं। आग लगाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि प्राथमिक स्तर पर ऐसे की बजह से आग लगाना मामना की जा रहा है।

रोहिणी कोर्ट में जज के चैबर में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में कार्यरत अंतिरिक सत्र न्यायाधीश भूर्पंदर सिंह के चैबर में बुधवार सुबह आग लग गई। उस समय सत्र न्यायाधीश अदालत कक्ष में मुकदमों पर सुनवाई कर रहे थे। अचानक करीब 11 : 10 बजे चैबर से धूंधा निकलते देखे अदालतकर्मी ने न्यायाधीश को इसकी सूचना दी। जिसके बाद फायर बिग्रेड को फॉन किया गया। यौक पर पहुंची फायर बिग्रेड की पांच गाड़ियोंने दूरपारी मजिल पर स्थित न्यायाधीश की चैंबर में लौंग आग पर कुछ ही देर में कालू पा लिया। हालांकि न्यायाधीश के चैंबर में रुखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। इसके न्यायाधीश का निजी सामान भी शामिल है। अपी फायरकर्मी ने पुलिस दोनों मौके पर हैं। आग लगाने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि प्राथमिक स्तर पर ऐसे की बजह से आग लगाना मामना की जा रहा है।



अशोक सप्तराषि बुद्ध विहार के द्वारा सुल्तानपुरी में बुद्ध पूर्णिमा पर भव्य शोभायात्रा व विशाल भण्डारे का आयोजन किया गया

भव्य शोभायात्रा का उद्घाटन कर्मसु अध्यक्ष, उपासिका श्रीमती बच्चन देवी भारती एवं संयोजक विजय कुमार भारती के सानिध्य में जय किशन, पूर्व विधायक, उपाध्यक्ष, कांग्रेस कर्मसु से रिबन काटवाकर शोभायात्रा का शुभारम्भ किया गया

नई दिल्ली। (सर्वांदाता:-महेन्द्र सिंह)

तथागत गौतम बुद्ध के जन्म महोत्सव / बुद्ध पूर्णिमा, दिनांक: 16 मई, 2022 दिन सोमवार के शुभ अवसर पर अशोक सप्तराषि बुद्ध विहार प्रबंध कर्मसु (पंजी.) के तत्त्वाधान में संस्थापक निर्वाण प्राप्त कैलाश चन्द्र भारती, अध्यक्ष, उपासिका श्रीमती बच्चन देवी भारती एवं संयोजक विजय कुमार भारती के सानिध्य में 20वीं, भव्य बुद्ध जयंति शोभायात्रा एवं विशाल भण्डारे का आयोजन किया गया। जिसमें धम्म बंधुओं ने नाच-गाकर, भोजन ग्रहण किया।

भव्य शोभायात्रा का उद्घाटन कर्मसु अध्यक्ष, उपासिका श्रीमती बच्चन देवी भारती एवं संयोजक विजय कुमार भारती के सानिध्य में जय किशन, पूर्व विधायक, उपाध्यक्ष, कांग्रेस कर्मसु से रिबन काटवाकर शोभायात्रा का शुभारम्भ किया गया। शोभायात्रा में बैण्ड बाजे, बागी और तथागत गौतम बुद्ध, डॉ. बी.आर. अंबेडकर, संस्थापक रव. कैलाश चन्द्र भारती एवं अनागरिक गीता भारती की प्रतिमा सुन्दर रूप से सुसज्जित की गई और रेकड़ी की सख्त्य में बौद्ध अनुयायी साथ-साथ बुद्ध और भीम के नारो के साथ शाति का संदेश देते हुए, यात्रा में चलते रहे और



जगह-जगह शोभायात्रा का सम्मान भी कुमार भारती, जयकिशन और अन्य बोद्ध किया गया, सोनू प्रधान के द्वारा अनुयायों का पगड़ी बांधकर स्वागत किया जगह-जगह जलपान व बच्चों के लिए फुट, जूस वितरण किए गए और सी-8 में और भीम के नारो के साथ शाति का संदेश देते हुए, यात्रा में चलते रहे और बालमिकी मंदिर कर्मसु के द्वारा विजय

जलपान की व्यवस्था की ओर जलेबी चौक पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कर्मसु उपाध्यक्ष जय किशन द्वारा जलपान, प्रसाद वितरण किया गया। जय किशन ने कहा बताया कि विश्व शांति के लिए भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर ही शांति स्थापित होगी, देश को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। शोभायात्रा का विशेष रूप से सहयोग बाहरी जिला, दिल्ली पुलिस, उपायुक्त के द्वारा भारी बल तैनात कर शोभायात्रा को सुरक्षा प्रदान की गई।

शोभायात्रा अशोक सप्तराषि बुद्ध विहार (मन्दिर) बी-2 ल्लॉक, सुल्तानपुरी से आंरम्भ होकर बी-4, सी-8, सी-9, सी-6 के बीच वाले रोड़ व थाने वाले रोड़ से निकलकर सी-2, सी-4 से होती हुई अंबेडकर पार्क से बी-4, बी-3, बी-1, बी-2, ए-4, ए-3, ए-1, ए-2, डी-1, ई और एफ ल्लॉकों के बीच वाले रोड़ से निकलती हुई अशोक सप्तराषि बुद्ध विहार पर समाप्त हुई शोभायात्रा में धम्म प्रेमी, महेन्द्र सिंह, ए.के.भारती, इन्द्रजीत, सञ्जू, हरपाल सिंह (पत्रकार), राजू भारती, राजू पेन्टर, कांति, प्रदीप (धन्यु), लोकेश गांधी, गौतम, देवेन्द्र, लक्ष्मन, महेश कुमार, चन्द्र, लेहरु, सुरज गुप्ता, लवली सिंह व अन्य सहित मौजूद थे।



सम्पादकीय बढ़ती नफ़रत के बीच भाईचारे का स्तंभ लखनऊ का बड़ा मंगल

हिंदुओं के भगवान के लिए मनाए जाने वाले बड़े मंगल की कहानी करीब 400 साल पुरानी है। जब पहले मुगल शासक नवाब मोहम्मद अली शाह के बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। कई जगह इलाज कराया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। इसके बाद नवाब की बेग़म रुबिया बेटे की सलामती के लिए मशत मांगने अलीगंज के हनुमान मंदिर पहुंची। कहा जाता है कि उस वक्त मंदिर के पुजारी ने उनके बेटे को मंदिर में ही छोड़ जाने के लिए कहा था।

मैं लखनऊ हूँ... मेरे दिल में आज भी हिंदू और मुसलमानों के लिए उतनी ही मुहब्बत है जितनी पहले हुआ करती थी। शायद मैं ही एक ऐसा शहर हूँ, जहाँ एक मुगल बादशाह की पत्नी अल्पाह के साथ बजरंग बली की भी डिवादत करती है। इस बात का जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में रहने वाले बाशिंदों ने अपने भाईचारे से मेरी संस्कृति

बीते दिनों कश्मीर में आतंकियों ने एक और कश्मीरी हिंदू रहुल भट्ट की उनके कार्यालय में घुसकर हत्या कर दी। इसी के साथ कश्मीरी हिंदुओं के कश्मीर लौटने की संभावनाएं तो स्थान हुई हीं, यह भी खतरा पैदा हो गया कि वहाँ जो बचे-खुचे कश्मीरी हिंदू हैं वे सही-सलामत रह पाएंगे। रहुल भट्ट की हत्या पर किसी सेक्युलर-लिबरल के चेहरे पर शिकन तक देखने को नहीं मिला। कश्मीर के नेताओं ने रसीद तौर पर चिंता जताई। कुछ ने तो रहुल की हत्या के लिए कश्मीर फाइल्स नामक उस फिल्म को दोष दिया, जो कश्मीर में रिलीज ही नहीं हुई, क्योंकि वहाँ सिनेमाघर ही नहीं। कई कुछ भी दावा करे, कश्मीर से भागे गए कश्मीरी हिंदुओं की वापसी तब तक संभव नहीं, जब तक कुछ वैसे कदम नहीं उठाए जाते, जैसे इजरायल ने अपने लोगों को अपनी भूमि में बसाने के लिए उठाए हैं। जैसे कश्मीरी हिंदुओं के घटी जाकर बसने के आसार नहीं, वैसे ही बालाल में वे कई लोग अपने धरों को लौटने की उमीद खो चुके हैं, जिन्हें पिछले विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने मार भगाया था। ये वे लोग हैं जो धोषित या फिर अधोषित तौर पर भाजपा, कांग्रेस या माकपा के बोटर थे। पिछले साल 2 मई को जैसे ही यह सप्त हुआ कि ममता बनर्जी फिर से सत्ता में आने जा रही हैं, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस के समर्थक विरोधी दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर टूट पड़े। उनके धरों-दुकानों पर हमले किए गए। उनकी महिलाओं से छेड़छाड़ और दुक्षर्म हुआ। उनकी संपत्ति लौटी या फिर जलाई। ये घटनाएं कई दिनों तक जारी रहीं, क्योंकि पुलिस ने मूकदर्शक बने रहना और हिंसक तत्वों के खिलाफ कुछ न करना ही बेहतर समझा। इस समझ के पीछे ममता का बार-बार यह कहना था

कि कहीं कोई हिसा नहीं हो सकता है और तोड़फोड़े, आगजनी की घटनाओं का जिक्र केवल उन्हें बदनाम करने के लिए किया जा सकता है। नवीजा यह हुआ कि बंगाल पुलिस और निकिय हो गई और हिस्क तत्वों का दुस्साहस चरम पर पहुंच गया। उन्होंने बाकायदा पर्चे बांटकर उन सबके सामाजिक बहिकार का अभियान छेड़ दिया, जिनके बारे में तनिक भी यह संदेश था कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। हर तरफ और यहां तक कि केंद्र सरकार से भी हताश-निराश और डेरे-सहमे लोगों ने जान बचाने और तृणमूल कांग्रेस के आतंक से बचने के लिए बंगाल छोड़ना ही बेतर समझा। जब ऐसे लोग असम पहुंचे और उनके बारे में वहां के अखबारों ने लिखा, तब देश को पता चला कि बंगाल में ‘खेला होवे’ के नाम पर क्या गुल खिलाया गया है? राजनीतिक हिसा के भय से इन लोगों का पलायन बंगाल ही नहीं, भारत के माथे पर भी एक कलंक था, लेकिन किसी को और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कोई फक्त नहीं पड़ा। आतंकियों, जालसाजों, दंगाइयों के मामलों को तत्पत्ता से सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में चुनाव बाद की भीषण हिसा का स्वतं संज्ञान लेने की जरूरत नहीं समझी। जब इस बारे में याचिकाएं दायर हुईं तो भी उन्हें सुनने की कोई तत्पत्ता नहीं दिखाई गई। गनीमत यह रही कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस हिसा का संज्ञान लिया। उसने हिसा, हत्या, दुश्कर्म, लूटपाट, आगजनी की जांच का काम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपा। इस आयोग ने अपनी जांच में कहा कि बंगाल में कानून का राज नहीं, सासकों का कानून चल रहा है। बंगाल सरकार के तमाम विरोध के बाद भी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव बाद हिसा की जांच सीबीआई को सौंपी और एक विरोध जांच दल

का गठन भी किया। सीबीआई ने चुनाव बाद हिंसा में लिस कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन यदि आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद हालात सामान्य हो गए होंगे, हिस्पूक तत्वों के दुसराहस का दमन हो गया होगा, ममता सरकार को लज्जा आई होगी और पलायन करने वाले लौट आए होंगे, तो यह जान लें कि ऐसा नहीं हुआ। चुनाव बाद हिंसा में जो लोग गिरफ्तार किए गए, उनमें से कई जमानत पाकर बाहर आ गए। उनकी धमक और उनका आतंक कायम है। उनके भय से कई पीड़ित परिवार एक साल बीत जाने के बाद भी अपने घरों को लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। जो चांद लोग माफी मांगकर और भाजपा या फिर माकपा को वोट देने को अपनी 'भूल' मानकर लौटे, उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित रखा गया। कुछ को दूसरे मोहल्ले में रहना पड़ रहा है तो कुछ को बार-बार अपना मकान बदलना पड़ रहा है। एक अंग्रेजी दैनिक के अनुसार कपीसी मैरिडिकल कालेज, जादवपुर के एक कमर्शियल को बोते एक साल में 12 बार घर बदलना पड़ा है। इसी दैनिक के अनुसार जादवपुर के 35 परिवार ऐसे हैं, जो पलायन के बाद अभी तक अपने घरों को नहीं लौट सके हैं। कुछ ने सदैव के लिए बंगाल छोड़ देना बहेतर समझा है। कुछ अपने दल के नेताओं के सहयोग से लौटे हैं, लेकिन डर के साथे में रह रहे हैं। क्या इससे भले म्यामार से मार भगाए गए रोहिण्या नहीं, जिनके बारे में कम से कम दुनिया बात तो करती है? खुद भारत में ऐसे कई 'मानवतावादी' हैं, जो भारत आ घुसे रोहिण्या को यहां बनाए रखने की चिंता में ढुबले हाते रहते हैं, लेकिन वे कभी बंगाल के प्रताड़ित-पीड़ित और पलायन करने वालों के बारे में एक शब्द नहीं कहते, क्यों? क्योंकि बांगाल में सेक्युलर सरकार है।

**कांग्रेस की किसी भी चिंता को नहीं
खत्म कर पाया चिंतन शिविर**

प्रेस का चिंतन-शिविर समाप्त हो गया लेकिन क्या वह उसकी फल नहीं थी? अंग्रेज ने दिल्ली के अपने शहरों की बदलाई दी थी।

कांग्रेस का वितन-नशवर समाप्त हो गया लाकन क्या वह उसका। समाप्त कर पाया? कांग्रेस की चिंता तो अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई। कांग्रेस की चिंता वास्तव में भारत के लोकतंत्र की भी चिंता है, क्योंकि शक्ति विरोधी दल के बिना कोई भी लोकतंत्र जल्दी ही प्रवाह परिवर्तित करता है। वैसा लोकतंत्र बिना ब्रेक की मोटर गाड़ी बन जाता है। किसी टार्टी को सशक्त होने के लिए नीति और नेता की जरूरत होती है। हम इस उदयपुर शिविर में से किस नीति का उदय हुआ है। सोनिया राजपांडित कहा कि अब कांग्रेस भारत जोड़े यात्रा चलाएगी। इस समय क्या उसे उठ रहा है? उसे जोड़ने की बजाय कांग्रेस को जोड़ना ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस अंदर और बाहर दोनों तरफ से टूट रही है। स्वयं राहुल गांधी ने अपने विषय पर विचारण में कहा है कि कांग्रेसी नेता हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मुझे जलाला? (वैसे सोनिया, राहुल और प्रियंका को तो यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है)। इसीलिए कांग्रेस हर प्रांत में अंदर से टूट रही है। मध्य प्रदेश की सरकार क्यों गिरी? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रीयों की विर्तियां क्यों डागमाती रहती हैं? कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री और मंत्री गड़कर विरोधी दलों में क्यों शामिल हो रहे हैं? इस वक्त कांग्रेस की सरकार वितन प्रांतों में है, वे प्रांतीय नेताओं के दम पर टिकी हुई हैं? इसीलिए राजपांडित का यह कहना तर्कसंगत नहीं लगता कि भाजपा से सिर्फ अंदर कांग्रेस ही लड़ सकती है, वह एक मात्र अखिल भारतीय विरोधी पार्टी है। और वह एक मात्र ऐसी पार्टी है, जिसके पास विचारधारा है। यहां कम्प्यूटरी का जिक्र जरूरी नहीं है लेकिन क्या यह सत्य है कि देश की सभी पार्टी पार्टी भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है? राहुल का कहना है कि भाजपा से सिर्फ सत्तालोभी और देशोदूष पार्टी है। क्या कांग्रेस सत्तालोभी भी नहीं है? भाजपा के पास तो सही या गलत, एक विचारधारा है लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? न उसके पास गांधीवाद है, न समाजवाद है, न गरीबी है। और न ही 'भारत को महासंपन्न बनाओ' या 'महाशक्ति बनाओ' है। उसके पास सिर्फ सत्तारुद्ध दलों की लचर-पचर आलोचना है, जो लोगों के देश से निकल जाती है। उसके नेताओं को इस समय देश की नहीं, खुब बहुत चिंता है। इसी चिंता ने इस महान पार्टी को अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। उसी की देखादेखी लगभग सभी प्रांतों में पारिवारिक पार्टी गढ़ी हो गई हैं। इस चिंतन शिविर में एक भी वक्ता की हिम्मत नहीं पड़ी है। इस पारिवारिक प्रपंच के बिरुद्ध मुहं खोले। यह सुसंयोग है कि वर्तमान तारुद्ध पार्टी अभी तक पारिवारिक प्रपंच में नहीं फंसी है, हालांकि वह गंभीर उसी रास्ते पर चल पड़ी है। 50 साल से कम आयु के लोगों ने मुख्ता देने का झारा तो ठीक है लेकिन उसमें से भी परिवारवाद का विचार नहीं है। 'एक परिवार, एक टिकिट' की बात, उसमें भी 5 वर्ष की क्या चोर दरवाजे से परिवारवाद को ही चलाना नहीं है?

मद्द की प्रतीक्षा में बंगाल की चुनावी हिंसा के पीड़ित

बीते दिनों कश्मीर में आतकियों ने एक और गयी विट मॉल प्रदूषक संस्करण कार्रवाई में शामिल कि कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही है और तोड़फोड़, अपाचनी वीर भगवानों का चिन्ह केवल उद्देश्यवाका गठन भी किया। सीबीआई ने चुनाव बाद हिंसा गें लिप्त कई लोगों को प्रियाप्त घिसा लेकिन यह

जानेजान का बटनाजा या जिजक करने उठ परदा करने के लिए किया जा रहा है। नीतीय यह हुआ कि बंगाल पुलिस और निहित हो गई और हिंसक तर्कों का दुस्साहस चरम पर पहुंच गया। उहोंने बाकायदा पर्चे बाटकर उन सबके सामाजिक बहिकार का अभियान छेड़ दिया, जिनके बारे में तनिक भी यह संदेह था कि उहोंने तृणमूल कांग्रेस को बोट नहीं दिया। हर तरफ और यहां तक कि केंद्र सरकार से भी हत्याश-निराश और डे-सहमें लोगों ने जान बचाने और तृणमूल कांग्रेस के आतंक से बचने के लिए बंगाल छोड़ना ही बेहतर समझा। जब ऐसे लोग असम पहुंचे और उनके बारे में वहां के अखबारों ने लिखा, तब देश को पता चला कि बंगाल में ‘खेला होवे’ के नाम पर क्या गुल खिलाया गया है? राजनीतिक हिंसा के भय से इन लोगों का पलायन बंगाल ही नहीं, भारत के माथे पर भी एक कलकथा, लैकिन किसी को और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आतंकियों, जालसाजों, दंगाइयों के मामलों को तत्परता से सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में चुनाव बाद की भीषण हिंसा का स्वतं संज्ञान लेने की जरूरत नहीं समझी। जब इस बारे में याचिकाएं दायर हुईं तो भी उन्हें सुनने की कोई तत्परता नहीं दिखायी गई। गनीमत यह रही कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस हिंसा का संज्ञान लिया। उसने हिंसा, हत्या, दुर्क्रम, लूटपाट, आगजनी की जांच का काम राष्ट्रीय मानवाधिकार अयोग को सौंपा। इस आयोग ने अपनी जांच में कहा कि बंगाल में कानून का गज नहीं, शासकों का कानून चल रहा है। बंगाल सरकार के तमाम विरोध के बाद भी कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपी और एक विशेष जांच दल न लाइ बढ़ रहा का नियन्त्रण किया, लोकनायक आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद हालात सामान्य हो गए होंगे, हिंसक तर्कों के दुस्साहस का दमन हो गया होगा, ममता सरकार को लज्जा आई होगी और पलायन करने वाले लौट आए होंगे, तो यह जान लें कि ऐसा नहीं हुआ। चुनाव बाद हिंसा में जो लोग गिरफ्तार किए गए, उनमें से कई जमानत पाकर बाहर आ गए। उनकी धमक और उनका आतंक कायम है। उनके भय से कई पीड़ित परिवार एक साल बीत जाने के बाद भी अपने घरों को लौटने की हिंसा नहीं जुटा पाए हैं जो चंद लोग माफी मांगकर और भाजपा या फिर माकां को बोट देने को अपनी ‘भल’ मानकर लौटे, उहोंने सरकारी योजनाओं से विचित्र रखा गया। कुछ को दूसरे मोहर्रें में रहना पड़ रहा है तो कुछ को बार-बार अपना मकान बदलना पड़ रहा है। एक अंग्रेजी दैनिक के अनुसार जादवपुर के 35 परिवार ऐसे हैं, जो पलायन के बाद अभी तक अपने घरों को नहीं लौट सके हैं। कुछ ने सदैव के लिए बंगाल छोड़ देना बेहतर समझा है। कुछ अपने दल के नेताओं के सहयोग से लौटे हैं, लैकिन डर के साथे में रह रहे हैं। क्या इससे भले म्यामार से मार भगाए गए रोहिण्या नहीं, जिनके बारे में कम से कम दुनिया बात तो करती है? खुद भारत में ऐसे कई ‘मानवतावादी’ हैं, जो भारत आ घुसे रोहिण्या को यहां बनाए रखने की चिंता में दुखले होते रहते हैं, लैकिन वे कभी बंगाल के प्रांतांडित-पीड़ित और पलायन करने वालों के बारे में एक शब्द नहीं कहते, क्यों? क्योंकि बंगाल में सेक्युलर सरकार है।

माहवारी अवकाश : वरदान या अभिशाप?

जुड़ी बच बता रही हैं कि जब माहवारी के गंभीर लक्षण देती हैं, तब उन्हें कसी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। वे कहती हैं मैं कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही थी, मेरा दर्द इतना ज था कि मेरी आंखों से अंसू आ गए थे और मैं समझ नहीं पाए रही थी कि मैं क्या करूँ। स्वाधारिक तौर पर युड़े वहां से जाना पड़ा। माहवारी से जुड़े अध्ययनों के लिए समग्र परीक्षण के मुताबिक, प्रजनन की उम्र की महिलाओं में से 91 फ़ीसदी डिसमेरोरिह्या से पीड़ित रहती हैं, जिसमें से 29 फ़ीसदी को बेहद तेज दर्द होता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ़ फैमिली फिजिशियन्स का फूहना है कि डिसमेरोरिह्या इतना गंभीर होता है कि यह 20 फ़ीसदी महिलाओं की रोजाना की गतिविधियों में प्रस्तरक्षण करता है। बर्च कहती हैं, मुझे उस स्थिति में सिर्फ़ बंवर्ष ही करना पड़ता है। मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती हूँ.... कुल मिलाकर मैं ठीक से काम ही नहीं कर पाती हूँ। बुनिया के कुछ देरों में महिलाएं अपनी माहवारी के दैर्घ्यना नहीं तौर पर दी गई छुट्टियां ले सकती हैं। लेकिन ऐसे माहवारी अवकाश की नीति विवादित है- इन पर लांचन नगाने और भेदभाव बढ़ाने के आरोप लगते हैं। यह तीव्र विवाद का विषय बन जाती हैं और माहवारी अवकाश पर यान ला पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद यूरोप में स्पेन इस तरह की छुट्टियां देने वाला फिलहाल देश साबित हो सकता है। लीक हुआ कानून का स्वास्थ्यावलोकन मसौदा, जिसे स्पेन में मंत्री परिषद के सामने लाया गया था, को पेश किया जाएगा, वह बताता है कि हर व्यक्ति ने तीन दिन की माहवारी छुट्टी मिलेगी। हालांकि अभी तक नहीं जानकारी साफ नहीं है, लेकिन इसके लिए महिलाओं को गंभीर मासिक धर्म के लक्षणों का अनुभव देना जरूरी है और इसके लिए उन्हें चिकित्सकीय वित्तीय समाप्ति भी दिखाना होगा। स्पेन के सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ़ वॉमेन (महिला संस्थान) की निदेशिका टोनी गोरिलियास ने स्पेन के ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट पब्लिको को बताया, हमारे देश में.... हमें यह हफ्तावाने में दिक्कत देती है कि मासिक धर्म एक शरीरिक प्रक्रिया है, जिसमें छुट्टी अधिकार होने चाहिए। मोरिक्यास ने ऐसा अंकड़े भी प्रकाश किए, जो बताते हैं कि दो में से एक महिला को दर्द और माहवारी का अनुभव होता है। डीबल्ट्यू ने संस्थान और स्पेन के समान मंत्रालय से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस पर टिप्पणी करने से कार कर दिया। बता दें यह संस्थान, समता मंत्रालय के

तहत ही आता है। नीति का मसीदा, जिसमें अब भी बदलाव किया जा सकता है, वह एक नए प्रजनन कानून का हिस्सा है, जो महिलाओं को गर्भपात की स्थिति में छुट्टी देने का प्रावधान करता है और 16 से 17 साल की महिलाओं को गर्भपात के लिए पालक की अनुमति की बाध्यता को खत्म करता है। यह कानून माहवारी से जुड़े उत्पादों, जैसे-पैड्स, टैंपॉन्स पर बिक्री शुल्क का खाता भी करता है। इटली की संसद ने 2017 में ऐसा ही मसीदा पेश किया था, जिस पर गहन बहस शुरू हुई थी कि क्या इससे काम की जगहों पर भेदभाव बढ़ेगा या नहीं? अखिरकार यह मसीदा आगे नहीं बढ़ा पाया। केवल कुछ ही देश- जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया और जाम्बिया के पास ही ऐसी राष्ट्रीय नीति है, जिसमें भ्रातान सहित माहवारी अवकाश दिया जाता है। इंडोनेशिया में किरेयन पार्टनर्स की सीईओ वेवे हिटिपेड ने कभी इस तरह की छुट्टियों लाभ उठाया था, अब नियोक्ता के तौर पर भी उहें इन छुट्टियों को देने की अनिवार्यता है। वे कहती हैं कि उहोंने इन छुट्टियों को वकत-वक्त पर इस्तेमाल किया है, क्योंकि उहें माहवारी के दौरान पेट में बहुत तेज दर्द होता था। वह कहती हैं, ठीक से बैठना भी बहुत मुश्किल होता था। अगर मुझे अपनी डेस्क या मेरे लैपटॉप के सामने रोज 8 से 9 घंटे बैठना पड़ता, तो मैं काम नहीं कर पाती थी। वह बहुत दर्द भरा समय होता था। हिटिपेड इस नीति को उनके लिए बहुत मददगार बताती है। वह कहती है कि हालांकि उन्हें कभी इन छुट्टियों को लेने या देने में दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब भी इन छुट्टियों को लेकर भेदभाव किया जाता है और लांघन लगाए जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं महिलाएं आलसी होती हैं और वे काम करना नहीं चाहतीं। उनके मुताबिक, फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं के साथ खासतौर पर ऐसा है, जहां उत्पादकता सीधे काम पर बिताए गए वक़्त से जुड़ी होती है। उत्पादन से जुड़े धंधों (जैसे फैक्ट्रियों) में काम करने वाली महिलाओं द्वारा छुट्टी लेने पर उनकी तरफ संशय से देखा जा सकता है। जापान ने 1947 में युद्ध के बाद सुधारों के दौरान माहवारी छुट्टियों को लागू किया था, लेकिन वहां छुट्टियां लेने की प्रवृत्ति पर नजर डालने से पता चलता है कि यह इतना आसान नहीं है। निकेंद्र द्वारा कवाए गए हालिया सर्वे के मुताबिक, सिर्फ 10 फ़र्सीदी महिलाएं ही माहवारी छुट्टियां ले रही हैं, जबकि सर्वे में शामिल 48

फीसदी महिलाएं इन्हें लेना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने कभी ली नहीं। क्योंकि उन्हें अपने पुरुष बौस के सामने इनके लिए आवेदन करने में ज़िंझक महसूस होती है, क्योंकि बहुत कम महिलाएं इसके लिए छुट्टी लेती हैं। उदारवादी छुट्टियों की नीति वाले यूरोपीय देशों में भी माहवारी को आधार बताकर छुट्टी लेना आम नहीं है। नीदरलैंड में 2019 में 30 हजार से ज्यादा डच महिलाओं के सर्वे में पाया गया कि माहवारी के दौरान सिर्फ 14 फीसदी ने ही काम से छुट्टी ली, इसमें से भी 20 फीसदी ने ही इसकी सही वज़ह बताई थी। 2020 में माहवारी अध्ययन पर प्रकाशित किताब में दर्ज एक गहन अकादमिक पेपर, काम की जगह पर माहवारी की छुट्टियों के फायदे और नुकसान को बताता है। इस तरह की नीतियों के नकारात्मक परिणामों में लिंग भेद बाले विचारों और व्यवहार का बढ़ना, जिससे लैंगिक सामाजीकण और माहवारी पर लाठन की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे लैंगिक वेतन का अंर बढ़ता है और माहवारी पर कहता है कि इस तरह के नकारात्मक सामाजीकरण थोपा जाता है। पेपर कहता है कि इस तरह के नकारात्मक सामाजीकरण में महिला भंगरता, उत्पादकता में कमी और भरोसे की कमी शामिल होती है, जबकि माहवारी के चिकित्सकीयकरण में माहवारी को नकारात्मक ढंग से एक बीमारी कहा जाता है, जिसे ठीक किए जाने की जरूरत है। जैसा पेपर में बताया है, माहवारी, ट्रांसजेंडर और ड्लिंगिं से भिन्न व्यक्तियों (नॅन-बाइनरी) में भी हो सकती है, उन्हें भी माहवारी छुट्टियां दी जानी चाहिए। बर्च के ब्लिटेन के नेटवर्क के अनुभव में अगर मासिक आधार पर महिलाएं नियमित छुट्टियां लेती हैं, तो उनमें से कई को काम की जगहों पर दूर्दात किया जाता है। उन्हें अनुशासित किया जाता है या नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह कहती है कि माहवारी अवकाश नीति को लागू करने की क्षमता देश-देश के हिसाब से भिन्न होगी और यह अमेरिका जैसे देशों में बहुत मुश्किल होगी, जो बहुत कम भुगतान अवकाश देते हैं। बर्च के लिए स्पेन का प्रस्ताव पर्याप्त नहीं है। वह कहती है, जब आपको हर महीने उस तरीके का दर्द होता है, तो तीन दिन कुछ भी नहीं है। जब एक महिला बिस्तर में लेटी होती है, तो वह अपने पेट के निचले में हिस्से में दर्द के वरक गर्म पानी की बोतल सटाकर रखती है। 10 में से एक महिला एडोमेंट्रियोसिस से पीड़ित होती है, जिसमें गर्भाशय के ऊतक, गर्भाशय के बाहर विकसित हो जाते हैं।

है। इस तरह की स्थिति माहवारी को बेहद पीड़ादायी बना सकती है। उनका मानना है कि काम के समग्र माहौल को गंभीर माहवारी लक्षणों वाली महिलाओं को सहूलियत देने के लिए ज्यादा लचीला बनाना होगा। 2020 के पेपर में यह भी एक बात थी, पेपर कहता है, अगर काम की जगह पर लचीलापन होता है, तो इससे आम तौर पर माहवारी से गुजरने वाली महिलाओं को लाघ होगा। (उदाहरण के लिए ज्यादा अवकाश दिया जाए, घर से काम करने की छूट दी जाए, मनमुताबिक ढांग से काम को माहवारी के दौरान ढाला जा सके)। और कुछ कंपनियां इस बिंदु पर काम करना शुरू कर रही हैं, यहां तक कि वे अपनी कंपनी नीतियों में इसे शामिल कर रही हैं। जोमेटो भारत के बाहर स्थित एक प्लेटफॉर्म है, जो खाना पहुंचाने के काम से जुड़ा हुआ है। कंपनी में अगस्त 2020 से माहवारी अवकाश की नीति अपनाई गई है। कंपनी की संचार प्रमुख वैदिका पाराशर इस ढांचे की व्याख्या करते हुए बताती हैं कि साल के दैरान 10 माहवारी छुट्टियां ली जा सकती हैं। यह घोषित अवकाश के अंतरिक्त अवकाश होता है। वह बताती हैं कि इसके लिए एक सम्मानित व्यवस्था की गई है। संबंधित कंमंचारी टीम चैट में लाल बूद वाले कैलेंडर का इमोजी बनाकर इस छुट्टी को ले सकता है, इसमें फिर कोई सवाल नहीं पूछे जाते। वे भी इसका इस्तेमाल करती हैं। उन दिनों में से किसी एक दिन मैं वह इमोजी भेजकर दर्शा देती हूं कि मैं आगे काम के लिए उपलब्ध नहीं हूं। मैंने देखा है कि बहुत सारे सहकर्मी इसका सम्मान करते हैं। जोमेटो में इस बहुत गंभीरता से लिया जाता है। वह बताती हैं कि माहवारी अवकाश लेने के लिए जोमेटो में कर्मचारियों को अपना स्टेट्स बलकर एक आंतरिक सिस्टम में लॉगइन करना होता है। कंपनी ने एक ऐसी संस्कृति बनाने की कोशिश की है, जहां माहवारी अवकाश से किसी भी तरह का लाञ्छन ना जोड़ा जा सके। यह नीति सभी लिंग पर लागू होती है, इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। आपको इसके बारे में असहज महसूस नहीं करना चाहिए। यह एक जैविक क्रिया है। वह आगे कहती हैं कि इस नीति को लागू करने से बल्कि कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि आई है। नीदरलैंड में महिलाओं के सर्वे से पता चला है कि गंभीर माहवारी के लक्षण के बावजूद 81 फीसदी महिलाएं काम पर आई हैं, उन दिनों की संख्या साल में औसतन नी है।

श्रीलंका की मौजूदा स्थिति खतरे से भरी

काम लिया है, लेकिन सचाई यही है कि रानिल विक्रमसिंघे को लेकर लोगों की आम धारणा तो यही है कि वह राष्ट्रपति के परिवार के करीबी हैं, और जिन पर राष्ट्रपति संकट के समय अपने परिवार की हिफ़ाजत और हित को लेकर भरोसा कर सकते हैं। सीधे-सीधे शब्दों में कहा जाये, तो यह स्थिति नवी बोतल में पुरानी शराब परोसने की तरह है। दूसरी तरफ़ फायदेमंद स्थिति यह है कि विक्रमसिंघे हालांकि प्रधान मंत्री का पाद छठी बार संभाल रहे हैं और उन्हें दिल्ली और पश्चिमी देशों में एक ऐसे शांत विचारक और काम करने वाले के रूप में स्वीकार्यता हासिल है, जिस पर इस लिहाज़ से भरोसा किया जा सकता है कि वह जल्दबाज़ी में फैसलों नहीं लेते। इस समय श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता की तत्काल ज़रूरत है और इस हिसाब से विक्रमसिंघे मुकुद बैठते हैं। दूसरी ओर, विक्रमसिंघे खुद भी एक बदनाम राजनेता रह हैं, जिन्होंने कभी भी बतौर प्रधान मंत्री अपना एक भी कार्यकाल पूरा नहीं किया है, और वह संसद में एक-व्यक्ति वाली पार्टी (स्वयं) की नुमाइंदाकरते हैं और राजनीतिक रूप से एक चुकी हुई ताकत है। जैसा कि कोलंबो के आर्किबिशप कार्डिनल मैल्कम रंजीथ कहते हैं, लोग सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति चाहते हैं, न कि ऐसा व्यक्ति, जो राजनीति में चुका हुआ हो। कोलंबो में इस बात को लेकर संदेह बना हुआ है कि राजपक्षे ने विक्रमसिंघे को मुख्य रूप से प्रदशनकारियों की खुद के बाहर किये जाने को मांग से ध्यान हटाने के लिए चुना है। बीबीसी ने बताया कि विक्रमसिंघे की नियुक्ति की यह खबर को श्रीलंका में

+ काफी हद तक निराशा और अविश्वास के साथ देखा गया है। यह आने वाले दिनों और हफ्तों में अहम हो जाता है, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन को शांति के साथ नये चुनाव कराने और नयी सरकार के गठन आदि की मुश्किल ज़िम्मेदारी विक्रमसिंघे के कंधों पर आ गयी है। लेकिन, बड़ा सवाल यही है कि क्या वह राजपक्षे को इस्तीफा देने के लिए राजी कर पायेंगे? इस बात की संभावना कहीं ज्यादा है कि राजपक्षे इसके बजाय विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए विक्रमसिंघे का इस्तेमाल सुक्ष्म दीवार की तरह करने की कोशिश करें, जिसका असली मक्सद प्रदर्शनकारियों की ओर से उनके गंदी छोड़ने की मांग को टालना है। यह कहना पर्याप्त होगा कि विक्रमसिंघे सरकार का भविष्य अंधकारमय है। यहां खतरा इस बात का है कि जो राजनीतिक परिदृश्य सामने आ रहे हैं, उनसे आर्थिक बहाती की संभावनायें कमज़ोर होंगी। समानांतर रूप से कार्यकारी राष्ट्रपति की शक्तियों पर पकड़ बनाये रखते हुए और राजपक्षे को इस्तीफा देने को लेकर एक तारीख मुकर्रर करते हुए और साथ ही कार्यकारी राष्ट्रपति के पद को खत्म करते हुए विक्रमसिंघे के लिए पूरक वित्त और आईएमएफ के साथ समझौते पर बातचीत कर पाना तकरीबन असंभव होने जा रहा है। आर्थिक एजेंटेज़ पर काम करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। लंबी अवधि के ढांचागत सुधारों के ब्यांगें पर आईएमएफ के साथ बातचीत करने के अलावा सरकार को अट्टकालिक तरलता को अर्थव्यवस्था में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से तत्काल पूरक वित्त की व्यवस्था करने, लेनदेनों को ऋण भुगतान में थोड़े समय देने

की इजाजत दिये जाने के लिए मनाने, करों को बढ़ाने और गैर-जरूरी सार्वजनिक खर्च में कटौती के लिए कई कानून तैयार करने की ज़रूरत होगी। बिना किसी संदेह के आईएमएफ ने पहले से ही अपनी वित्तीय मदद पाने के लिए जरूरी सुधारों के ब्योरे को रख दिया है, जिसमें बजट में कटौती से लेकर आयकर और वैट में बढ़ोत्तरी, केंद्रीय बैंक की ओर से की जाने वाली मुद्रा की छापाई से पैदा होने वाली मुद्रास्फीति को खत्म करने, आयात प्रतिबंधों को समाप्त करना, रुपये को स्थिर करने के मकासद से सरकारी हस्तक्षेप को रोकने, और सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों की लिक्री या आर्थिक निजीकरण करने, भारी पड़ने वाले सामाजिक सविस्तरी को हटाने, और विकास को बढ़ावा देने वाले ढांचागत मुधार-जैसे चरणबद्ध उपायों की एक लंबी श्रृंखला शामिल है। जहां तक राजपक्षे का सवाल है, तो खासकर तब भी वह सत्ता में बने रहने के लिए दूढ़संकल्प हैं, जब जनता ने उह्ये और उनके परिवार को कथित भ्रष्टाचार और दूसरे अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराने की मांग की है। उह्योंने अपने पद से इस्तीफा देने का कोई इशारा नहीं जताया है और इसके बजाय उह्योंने अपनी कार्यकारी शक्तियों को अस्पष्ट रूप से कम किये जाने का विचार रखा है। स्थिति बेहद अस्थिर है। और अगर इस राजनीतिक गतिरोध को जल्दी से सुलझा नहीं लिया जाता है, तो आर्थिक तबाही और भी गहरी हो सकती है या पहले से कहीं ज्यादा सामाजिक उपद्रव की संभावना बन जाती है। राष्ट्रपति राजपक्षे को हटाने या दरकिनार करने की प्रक्रिया में किसी तरह महीनों नहीं, तो हमें तो लग ही सकते हैं और सभव है-

कि यह कवायद ही पूरी तरह से नाकाम हो जाये। यही वह स्थिति हो सकती है, जब राजपक्षे हिंसक दमन (अपने पिछले रिकॉर्ड के अनुरूप) का सहारा लेकर या हुक्मूत में सेना को एक बड़ी भूमिका देकर इस उथल-पुथल को अपने मक्सद में बदलने के लिहाज़ से इस पल का अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। शीर्ष सैन्य कमांडों, खासक सेना प्रमुख, मेजर जनरल शैवेंद्र सिंह्या और रक्षा सचिव, सेवानिवृत्त जनरल कमल गुणरत्ने को राष्ट्रपति के करीबी वरूप में जाना जाता है। श्रीलंका के सैन्य कर्मी सुविधाओं और विशेषाधिकारों वाला जीवन जीते हैं और प्रभावित होने वाले के रूप में उन्हें इस हुक्मूत की हिक्काज़त के लिए अपनी बंदूकों की नाल प्रदर्शनकारियों को तरफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेशक, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका प्रासारिक तो है, लेकिन इसे बढ़ा-चढ़ाकर भी पेश नहीं किया जाना चाहिए। सैन्य नेतृत्व को राजनीति में हस्तक्षेप करने या हुक्मूत के समर्थन में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के क्रूर दमन से रोकने की संभावना तो नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा सेना प्रमुख पहले से ही कथित युद्ध अपराधों (गृहयुद्ध के दौरान बतौर रक्षा सचिव गोटाबाया राजपक्षे की निगरानी में किये गये अपराधों) के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। विरोधाभास्म रूप से औसत श्रीलंकाई लोगों की आर्थिक कठिनाइयों को कम करने और राजनीतिक बदलाव के लिए चल रहे उपद्रव की तीव्रता को कम करने के लिहाज़ से आई-एम-एफ अगर कोई कदम उठाता है, तो इससे राजपक्षे को सास लेने की भी जगह मिल सकती है, जिससे उन्हें और उनके परिवार

मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल व मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन के सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, सी.डी-2 में करोड़ो का भ्रष्टाचार जारी.....सी.बी.आई जांच की मांग ।

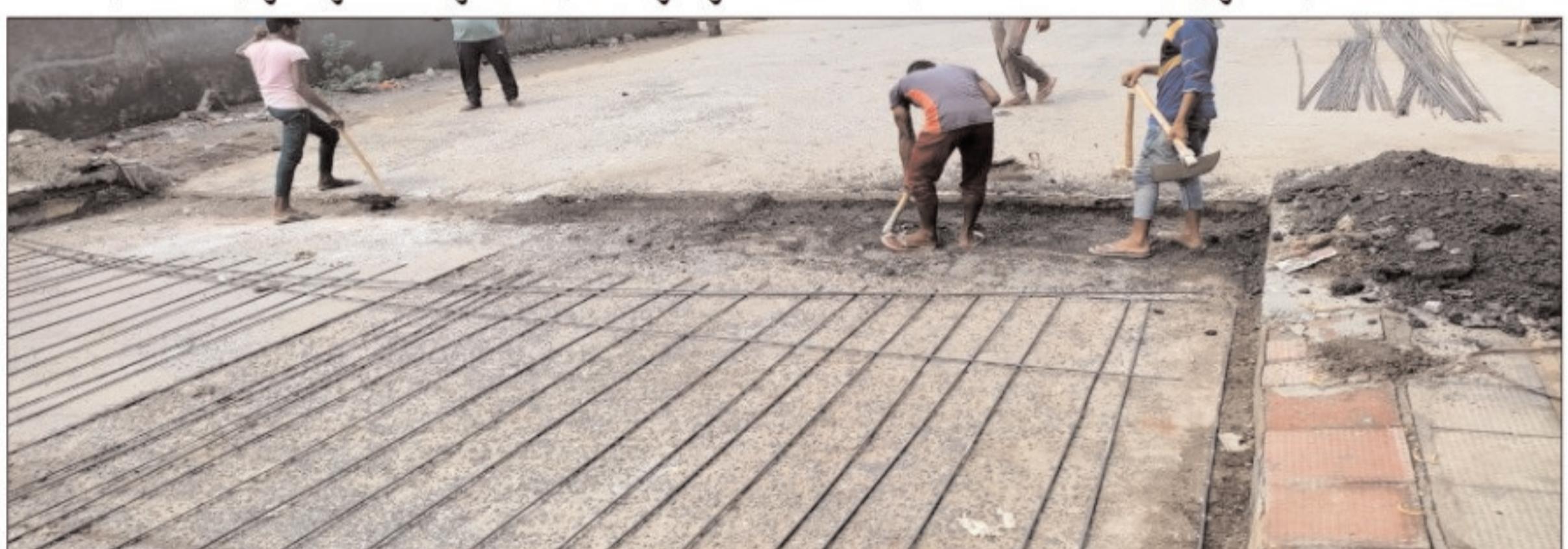
दिल्ली प्रशासन ने भ्रष्ट ई.ई सुधीर आर्य, सतर्कता/ई.ई अशोक कुमार के आगे टेके घुटने

कार्यपालक, सहायक व कनिष्ठ अभियंता बने भ्रष्टाचारी नंम्बर-1

सी.डी-2 के पूर्व ई.ई अशोक कुमार, वर्तमान ई.ई सुधीर आर्य, ए.ई जुबैर खान, राशिद अली, जे.ई सतीश कुमार ने किए करोड़ो के वारे न्यारे...

विकास एवं निर्माण कार्यों में घोटाला कर लगाई गई व लगाई जा रही,
बेहद घटिया निर्माण सामग्री की शिकायतों के आगे केजरीवाल प्रशासन ने टेके घुटने

ए-बी एक्स, ए-2 लॉक, सुल्तानपुरी व मंगोलपुरी को जोड़ने वाले मुख्य पुल निर्माण में लगाई बेहद घटिया निर्माण सामग्री, पुल में पढ़ी दरारे व एक ओर से धंसा



शिकायते होती रही, परन्तु भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार बढ़ता रहा, आज भी नहीं लगी रोक।

अध्यक्षः अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा

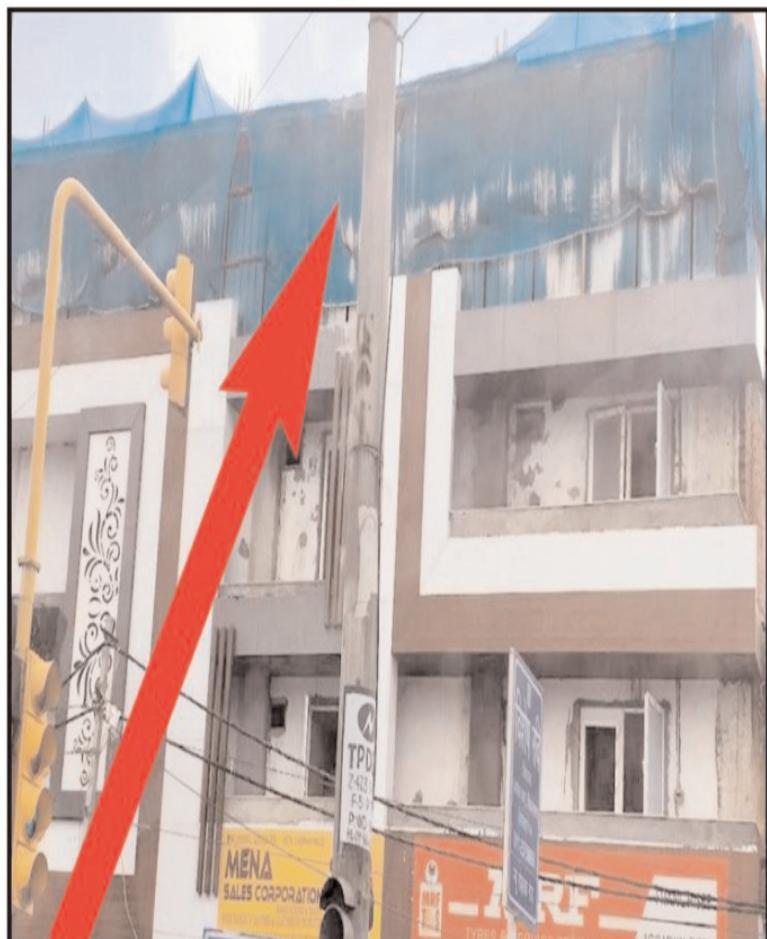
विज्ञापन-जनहित में जारी.....

निगम में भाजपा की छवि को कालिक पोत रहे हैं भ्रष्ट अभियंता

करोल बाग जोन, भवन विभाग बना भ्रष्टाचार का अड्डा!

अवैध निर्माण की काली कमाई से अभियंता से उपायुक्त तक बने “अडानी”

उ.दि.न.नि के मुख्य सतर्कता अधिकारी मंगेश कश्यप बने मूक दर्शक कब तक चलता रहेगा भ्रष्टाचार का खेल



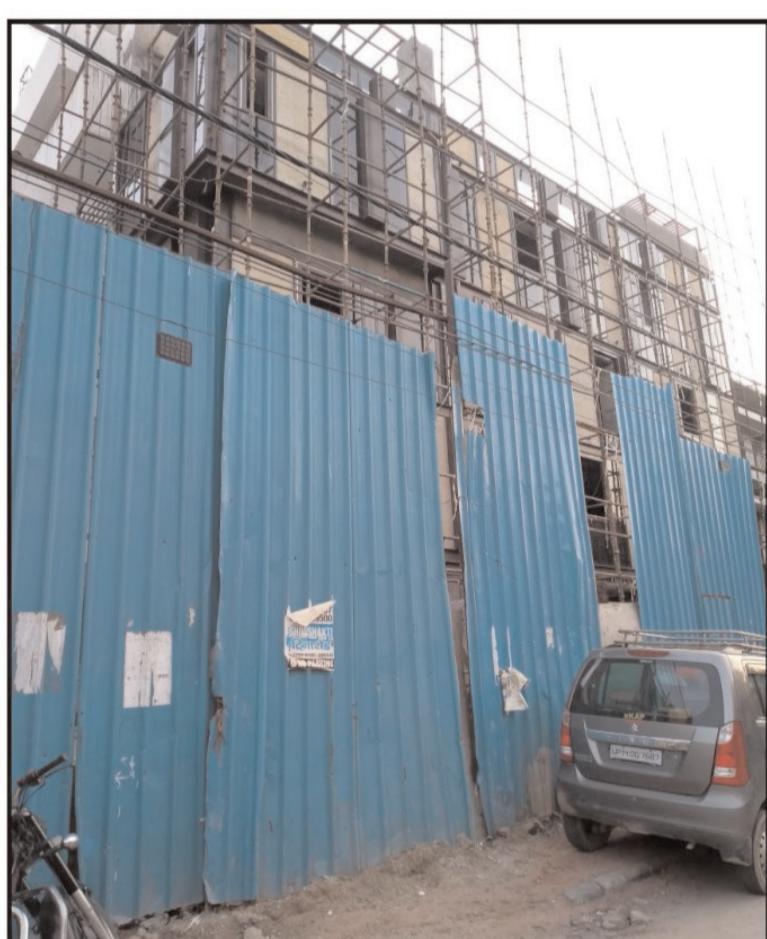
करोल बाग, नई दिल्ली



करोल बाग, नई दिल्ली



करोल बाग, नई दिल्ली



करोल बाग, नई दिल्ली



करोल बाग, नई दिल्ली



करोल बाग, नई दिल्ली

करोल बाग जोन में बिल्डर माफिया का राज सारे वार्ड बनते जा रहे हैं स्लम युक्त हर वार्ड में चार से पांच मंजिला, बेसमेन्ट सहित अवैध निर्माण धड़लो से किया जा रहा है। अभियंताओं की काली कमाई चल-अचल व बेनामी सम्पत्ति की श्रीमान निदेशक जी, सीबीआई, भारत सरकार से जांच की मांग।

अध्यक्ष: अपराध एवं भ्रष्टाचार निरोधक मोर्चा